

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डीबी विशेष अपील रिट संख्या 659/2015

ब्रज मोहन सिंह बारेठ पुत्र श्री बीडी बारेठ, उम्र लगभग 76 वर्ष, निवासी 277, प्रेम नगर, जगतपुरा, जयपुर

----अपीलकर्ता

बनाम

1. सचिव, कार्मिक विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से राजस्थान राज्य।
2. निदेशक पेंशन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री त्रिभुवन नारायण सिंह
प्रतिवादी के लिए(ओं) के लिए : श्री विज्ञान शाह, एएजी की ओर से
श्री यश जोशी और श्री पुलकित भारद्वाज

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्रीमान. मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय श्री. जस्टिस आशुतोष कुमार

आदेश

प्रकाशनीय

11/09/2024

1. सुना
2. इस अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का विरोध किया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 08.12.2000 के उस आदेश को चुनौती देने के संबंध में दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी ने विभागीय जाँच में लापरवाही/कदाचार के आरोपों के आधार पर अपीलकर्ता की 100% पेंशन रोकने का निर्देश दिया था। यह जाँच अपीलकर्ता/अपराधी कर्मचारी के सेवाकाल के दौरान सेवानिवृत्ति से पहले शुरू की गई थी।

3. तत्काल अपील पर निर्णय लेने और विचारार्थ उठने वाले विधिक मुद्दों के लिए आवश्यक सर्वोत्कृष्ट तथ्य यह है कि जब अपीलकर्ता राज्य सरकार की सेवाओं में आरएएस (चयन वेतनमान) के सदस्य के रूप में कार्यरत था, तो उसे 30.03.1993 को एक आरोप-पत्र जारी किया गया, जिसमें नौ आरोप लगाए गए थे। जाँच अधिकारी की नियुक्ति के बाद, जाँच जारी रही। हालाँकि, इसके निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले ही, अपीलकर्ता 29.02.1996 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया। जाँच अधिकारी ने अपनी जाँच रिपोर्ट 31.07.1996 को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को प्रस्तुत की। सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद की अवधि के दौरान, अपीलकर्ता 01.03.1996 से अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहा था। जाँच अधिकारी ने आरोपों को साबित पाया और अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने 12.11.1997 को अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें अपीलकर्ता से पांच साल के लिए 100% पेंशन रोके जाने के प्रस्तावित दंड/सजा के खिलाफ कारण बताने की अपेक्षा की गई। अपीलकर्ता ने कारण बताओ नोटिस पर अपना जवाब दाखिल किया। इसके बाद, 10.04.1999 को एक नया कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें अब आजीवन 100% पेंशन रोके जाने का प्रस्ताव था। अपीलकर्ता ने फिर से कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी, उत्तर से असंतुष्ट और अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए विभिन्न आरोपों पर जाँच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमति जताते हुए, 08.12.2000 को दंड का आदेश पारित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने रिट याचिका दायर की, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश और राज्यपाल द्वारा पारित आदेश की सत्यता और वैधता पर प्रश्न उठाते हुए तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश इस आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है कि राजस्थान सेवा नियम, 1951 (संक्षेप में '1951 के नियम', जैसा कि शक्ति प्रयोग की तिथि पर विद्यमान था) के नियम 170 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने के लिए आवश्यक संतुष्टि प्राप्त करना आवश्यक था, जिसे अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया गया है, और ऐसी संतुष्टि के लिए कोई कारण भी नहीं दिया गया है। यह तर्क दिया गया है कि 1951 के नियम 170 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग पेंशन को पूर्णतः या आंशिक रूप से रोकने के लिए तभी किया जा सकता है जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह संतुष्टि दर्ज की गई हो कि यह गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही का मामला है, जिसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी पेंशन को पूर्णतः या आंशिक रूप से

रोकने की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और सरकार को हुई किसी भी आर्थिक हानि की वसूली का निर्देश भी दे सकता है। न तो आरोपों में इसे गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही का मामला बताया गया है और न ही जाँच अधिकारी द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज किया गया है। सक्षम प्राधिकारी ने अभिलेखों में उपलब्ध किसी भी सामग्री के आधार पर कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि यह गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही का मामला था। इसलिए, आक्षेपित आदेश कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का दूसरा निवेदन यह है कि 1951 के नियम 170 के तहत प्रदत्त शक्ति, मूलतः राज्यपाल के पास आरक्षित शक्ति है कि वह सरकार को हुई आर्थिक हानि की वसूली के लिए ही पेंशन रोके और जब तक आरोप न हों और सरकार को हुई आर्थिक हानि का निष्कर्ष न हो, केवल इसलिए कि दोषी कर्मचारी कदाचार या लापरवाही का दोषी पाया जाता है, पेंशन को पूर्णतः या आंशिक रूप से रोकने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

6. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तीसरा तर्क यह है कि जांच अधिकारी द्वारा दर्ज आरोपों और निष्कर्षों में भी अपीलकर्ता की ओर से कथित कदाचार/लापरवाही के कारण सरकार को हुई किसी भी आर्थिक हानि का कोई उल्लेख नहीं है।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 1951 के नियम 170 के तहत अपेक्षित संतुष्टि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत दर्ज की गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, जब यह पाया गया कि अपीलकर्ता अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है, तो 1951 के नियम 170 के तहत जांच की गई, जो एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के मामले में लागू होता है और जांच अधिकारी के निष्कर्षों से सहमत होने के बाद अपीलकर्ता को जुर्माना लगाने का प्रस्ताव करते हुए एक कारण बताओ नोटिस दिया गया था। जवाब प्राप्त होने के बाद, जब प्राधिकारी ने अपना दिमाग लगाया, तो पाया गया कि यह एक ऐसा मामला है जहां "कदाचार/लापरवाही की गंभीरता को देखते हुए", अपीलकर्ता के जीवनकाल के दौरान पूरी पेंशन रोकना न्यायोचित और उचित माना गया। इस प्रयोजन के लिए भी उसे कारण बताओ नोटिस दिया गया था और उसके बाद सक्षम प्राधिकारी ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के बाद और इसे गंभीर कदाचार का मामला पाते हुए, 1951 के नियम 170 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कार्यवाही की।

8. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि चूँकि सक्षम प्राधिकारी ने अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों के संबंध में जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए दोषसिद्धि के निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की थी, इसलिए सक्षम प्राधिकारी के लिए प्रत्येक आरोप पर स्वतंत्र रूप से दोषसिद्धि का निष्कर्ष दर्ज करना आवश्यक नहीं था। प्राधिकारी ने आक्षेपित आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज किया है कि आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आजीवन संपूर्ण पेंशन रोकने का निर्णय लिया गया है। अतः, आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई क्षेत्राधिकार संबंधी अवैधता या विकृतता नहीं है और विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आदेश को सही ठहराया है।

9. इस अपील में विचारणीय एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1951 के नियम 170 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके आजीवन सम्पूर्ण पेंशन रोकने का कानूनी औचित्य था।

10. सामान्यतः, जब किसी सरकारी कर्मचारी पर सेवाकाल के दौरान कदाचार और/या लापरवाही का आरोप लगाया जाता है, तो राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 (संक्षेप में '1958 के नियम') प्रक्रिया और लगाए जा सकने वाले दंड का निर्धारण करते हैं। 1958 के नियमों के नियम 14 में उन दंडों की प्रकृति सूचीबद्ध है जो किसी दोषी कर्मचारी पर कदाचार/लापरवाही का दोषी पाए जाने पर लगाए जा सकते हैं।

11. हालाँकि, ऐसे मामले में जहाँ विभागीय जाँच शुरू की जाती है, लेकिन पूरी नहीं होती है और दोषी कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाता है, विभागीय जाँच के संचालन को विनियमित करने वाले नियम, जैसा कि 1958 के नियमों के तहत प्रदान किया गया है, लागू नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में, राज्यपाल पेंशन को पूरी तरह या आंशिक रूप से रोकने की शक्ति अपने पास सुरक्षित रखते हैं, साथ ही सरकार को हुई आर्थिक हानि की वसूली का आदेश भी दे सकते हैं। पेंशन रोकने की यह योजना राजस्थान सेवा नियम, 1951 (खंड I - भाग-B) के नियम 170 के तहत प्रदान की गई है। राजस्थान सेवा नियमों का उपरोक्त भाग विशेष रूप से "पेंशन नियम" शीर्षक के अंतर्गत पेंशन मामलों से संबंधित है। किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद, उसके विरुद्ध केवल 1951 के नियमों के नियम 170 के तहत ही कार्यवाही की जा सकती है। वर्तमान मामले के निर्णय के लिए प्रासंगिक नियम, नीचे उद्धृत है :-

“170. पेंशन से हानि की वसूली।- राज्यपाल अपने पास पेंशन या उसके किसी भाग को, चाहे स्थायी रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए, रोकने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है और सरकार को हुई किसी भी आर्थिक हानि की पूरी या आंशिक राशि की पेंशन से वसूली का आदेश देने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है, यदि किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में पेंशनभोगी को उसकी सेवा अवधि के दौरान, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पुनः नियोजन पर की गई सेवा भी शामिल है, गंभीर कदाचार या लापरवाही का दोषी पाया जाता है:-

(क) बशर्ते कि ऐसी विभागीय कार्यवाही, यदि अधिकारी के सेवा में रहते हुए, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पहले या उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान, संस्थित की गई हो, तो अधिकारी की अंतिम सेवानिवृत्ति के पश्चात् इस नियम के अधीन कार्यवाही समझी जाएगी और उसे उस प्राधिकारी द्वारा जारी रखा जाएगा और समाप्त किया जाएगा जिसके द्वारा उसे उसी प्रकार प्रारंभ किया गया था मानो अधिकारी सेवा में बना रहा हो;

(ख) ऐसी विभागीय कार्यवाही, यदि अधिकारी के सेवाकाल के दौरान, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व या उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान, संस्थित नहीं की गई हो,-

(i) राज्यपाल की मंजूरी के बिना स्थापित नहीं किया जाएगा ;

(ii) ऐसी किसी घटना के संबंध में नहीं होगा जो ऐसी संस्था के गठन से 4 वर्ष से अधिक पूर्व घटित हुई हो; और

(iii) ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान पर किया जाएगा जैसा राज्यपाल निर्देशित करें और विभागीय कार्यवाहियों पर लागू प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जिसमें अधिकारी के सेवाकाल के दौरान उसके संबंध में सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया जा सकता है;

(ग) ऐसी कोई न्यायिक कार्यवाही, यदि अधिकारी के सेवाकाल के दौरान, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व या उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान, संस्थित नहीं की गई है, तो ऐसे बाद हेतुक के संबंध में संस्थित नहीं की जाएगी जो ऐसे संस्थित होने से 4 वर्ष से अधिक पूर्व उत्पन्न हुआ हो या कोई घटना घटित हुई हो; और

(घ) अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

12. उपर्युक्त प्रावधान की तर्कसंगत और तार्किक व्याख्या से यह स्पष्ट है कि राज्यपाल के पास पेंशन या उसके किसी भाग को, चाहे स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए, रोकने या वापस लेने की शक्ति सुरक्षित है और साथ ही सरकार को हुई किसी भी आर्थिक हानि की पूरी या आंशिक राशि

को पेंशन से वसूलने का आदेश देने का अधिकार भी है, यदि विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में पेंशनभोगी को उसकी सेवा अवधि के दौरान गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही का दोषी पाया जाता है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पुनः रोजगार पर दी गई सेवाएं भी शामिल हैं।

13. उपर्युक्त नियमों से जुड़ा पहला प्रावधान यह भी स्पष्ट करता है कि ऐसी विभागीय कार्यवाही, यदि अधिकारी के सेवाकाल के दौरान शुरू की गई हो, चाहे वह उसकी सेवानिवृत्ति से पहले हो या उसकी पुनर्नियुक्ति के दौरान, अधिकारी की अंतिम सेवानिवृत्ति के बाद इस नियम के तहत कार्यवाही मानी जाएगी और उसे उस प्राधिकारी द्वारा जारी रखा जाएगा और समाप्त किया जाएगा, जिसके द्वारा उसे उसी तरह शुरू किया गया था जैसे कि अधिकारी सेवा में बना रहा हो।

14. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि कोई कर्मचारी अपने विरुद्ध शुरू की गई विभागीय जांच पूरी होने से पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है, तो जांच केवल 1951 के नियम 170 के तहत निर्धारित तरीके से ही आगे बढ़ाई जा सकती है, न कि 1958 के नियम 170 के तहत।

15. इसके अलावा, नियम 1951 के नियम 170 के तहत पारित किए जा सकने वाले आदेश को भी नियम निर्माण प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है। इसमें पेंशन या उसके किसी भाग को स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए रोकना या वापस लेना शामिल हो सकता है और साथ ही, उपयुक्त मामलों में, जहाँ यह पाया जाता है कि सरकार को कोई आर्थिक हानि हुई है, वसूली का भी आदेश दिया जा सकता है। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि कदाचार या लापरवाही के सबूत पर पारित किए जा सकने वाले आदेशों की प्रकृति, दंड की प्रकृति से पूरी तरह भिन्न और अलग है, जो अन्यथा उन मामलों में नियम 1958 के नियम 14 के तहत लगाया जा सकता है जहाँ दोषी कर्मचारी सेवा में बना रहता है और उसकी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं हुई है।

16. नियम निर्माण प्राधिकारी ने अपनी बुद्धिमत्ता से, 1951 के नियम 170 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्रावधान किया है कि किसी पेंशनभोगी को उसकी पेंशन से पूर्णतः या आंशिक रूप से वंचित करने, या सरकार को हुई किसी हानि की वसूली के लिए, यह संतुष्टि दर्ज की जानी चाहिए कि सेवानिवृत्त कर्मचारी गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही का दोषी है, वह भी उसकी सेवा अवधि के दौरान की गई, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति पर दी गई सेवाएँ भी शामिल हैं। इसलिए, कानून की आवश्यकता यह है कि इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाए कि गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही की गई

है। 1951 के नियम 170 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने के लिए केवल यह पर्याप्त नहीं है कि कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी, विभागीय जाँच में, कदाचार या लापरवाही का दोषी पाया जाता है। 1951 के नियम 170 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने के लिए, सामान्य कदाचार या लापरवाही से अधिक कुछ देखा जाना आवश्यक है। प्रावधान स्पष्ट रूप से सक्षम प्राधिकारी को अपनी संतुष्टि दर्ज करने के लिए बाध्य करते हैं कि यह केवल कदाचार या लापरवाही का मामला नहीं है। यह केवल एक ऐसा मामला नहीं है जहाँ दोषी कर्मचारी को कदाचार या लापरवाही का दोषी पाया गया हो, बल्कि यह उससे भी बढ़कर, गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही का मामला है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस नियम का उद्देश्य पेंशनभोगी को उसकी पेंशन से वंचित न करना है, जो एक गंभीर मामला है और इसमें गंभीर नागरिक परिणाम शामिल हैं, जब तक कि उसे गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही का दोषी न पाया जाए।

17. 1951 के नियमों के नियम 170 में, चाहे अलग से पढ़ा जाए या 1958 के नियमों में निहित प्रावधानों के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो जांच अधिकारी को ऐसे निष्कर्ष दर्ज करने के लिए बाध्य करता हो क्योंकि कार्यवाही की प्रकृति में, इस प्रकृति की स्थिति किसी सरकारी कर्मचारी के सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद ही आएगी। इसलिए, प्रावधान के तर्कसंगत निर्माण पर, हमें यह मानना होगा कि 1951 के नियमों के नियम 170 के तहत जो संतुष्टि की परिकल्पना की गई है, उसे उस प्राधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए जो पेंशन रोकने या आर्थिक नुकसान की वसूली का निर्देश देने का निर्णय लेता है। इसके अलावा, उन गंभीर परिणामों को ध्यान में रखते हुए जो तब होते हैं जब एक पेंशनभोगी अपनी पेंशन से वंचित होता है या अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वसूली का आदेश भुगतता है, संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता कि यह गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही का मामला है, खाली औपचारिकता नहीं है। सक्षम प्राधिकारी कानून की भावना के अनुसार, परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष दर्ज करने के लिए बाध्य है, ताकि उन पर विचार करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, जो प्रकृति में बाह्य न हों, बल्कि मामले के लिए प्रासंगिक हों, कि मामला गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही की प्रकृति का हो और कदाचार या लापरवाही के एक सामान्य मामले तक सीमित न हो।

18. कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में, जहाँ केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (संक्षेप में '1972 के नियम') के पैरा मेटेरिया नियम 9 के तहत पेंशन रोकने के आदेश पर आपत्ति की गई थी,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि गंभीर कदाचार का निष्कर्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए, न कि जाँच अधिकारी द्वारा। टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं:-

“14. 1972 के नियमों के नियम 9 का अवलोकन करने के बाद, हमारे लिए अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रथम तर्क को स्वीकार करना संभव नहीं है। जाँच अधिकारी का दायित्व, किसी दोषी कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संदर्भ में, उसकी निर्दोषता या दोष का निर्धारण करने तक सीमित है। आरोपों (यदि कोई हों) के सिद्ध होने पर ही दंड प्राधिकारी यह निष्कर्ष दर्ज करेगा कि दोषी ने "गंभीर कदाचार" या "गंभीर लापरवाही" के कृत्य किए हैं, चाहे निष्कर्षों से यह निष्कर्ष निकलता हो या नहीं। दंड प्राधिकारी द्वारा ऐसे निर्धारण पर ही 1972 के नियमों के नियम 9 को लागू किया जा सकता है, यदि दोषी कर्मचारी इस बीच, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो गया हो। यह कोई विवाद का विषय नहीं है कि जब 30.11.2005 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को दंड दिया गया था, तब अपीलकर्ता 15 जून, 2005 को अधिवर्षिता प्राप्त करके सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका था। 30.06.2002. इसलिए हमें अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रथम तर्क में कोई योग्यता नहीं दिखती।”

19. इसलिए, जाँच अधिकारी का दायित्व, दोषी कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संदर्भ में, उसकी निर्दोषता या दोष का निर्धारण करने तक सीमित है। दंड देने वाले प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करे कि क्या निष्कर्ष से यह निष्कर्ष निकलता है कि दोषी कर्मचारी ने "गंभीर कदाचार" या "गंभीर लापरवाही" का कार्य किया है।

20. अब हम दिनांक 12.11.1997 और 10.04.1999 के कारण बताओ नोटिसों की विषय-वस्तु पर गौर करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस पहलू पर विचार करने को दर्शाता है कि क्या आरोपों की प्रकृति और अपीलकर्ता द्वारा कथित रूप से किए गए कदाचार/लापरवाही की सीमा के आलोक में यह गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही का मामला है। दोनों कारण बताओ नोटिसों के अवलोकन से केवल यह पता चलता है कि सक्षम प्राधिकारी ने जाँच रिपोर्ट और उसके निष्कर्ष का हवाला दिया और उसके बाद अपीलकर्ता को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए आदेश पारित करने का प्रस्ताव दिया। दिनांक 12.11.1997 के पहले कारण बताओ नोटिस में पांच साल के लिए पूरी पेंशन रोकने का प्रस्ताव था, लेकिन दिनांक 10.04.1999 के दूसरे कारण बताओ नोटिस में आजीवन पूरी पेंशन रोकने का प्रस्ताव था। दोनों कारण बताओ नोटिसों में, सक्षम प्राधिकारी ने किसी भी सामग्री या विचार के आधार पर कोई कारण दर्ज नहीं किया कि प्राधिकारी

इस मामले को न केवल कदाचार और/या लापरवाही का मामला क्यों मानता है, बल्कि इसे गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही का मामला क्यों मानता है। अपीलकर्ता ने अपना जवाब प्रस्तुत किया और उसके बाद, पेंशन रोकने का विवादित आदेश 08.12.2000 को पारित किया गया।

21. यदि हम उक्त आदेश को पढ़ें, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस बात पर शायद ही कोई विचार किया गया है कि इसे गंभीर कदाचार का मामला क्यों माना जाना चाहिए और यदि ऐसा है, तो ऐसी संतुष्टि या निष्कर्ष को उचित ठहराने के लिए सहायक कारण और उपस्थित परिस्थितियां क्या हैं।

22. प्रतिवादियों के विद्वान वकील का यह निवेदन कि आदेश से यह संकेत मिलता है कि प्राधिकारी ने आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए शक्ति का प्रयोग किया है, हमारे विचार में, 1951 के नियम 170 के तहत परिकल्पित कानूनी आवश्यकता या संतुष्टि को पूरा नहीं करता है।

23. हम पाते हैं कि आदेश में एक या दो स्थानों पर, केवल "आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए" कहा गया है। यह अपने आप में संतुष्टि दर्ज करने की कानूनी आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। यह केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया एक सरसरी संदर्भ था, बिना किसी चर्चा के, यद्यपि संक्षेप में, कि वर्तमान मामले को गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही का मामला क्यों माना जाता है। संक्षेप में, सक्षम प्राधिकारी ने जाँच अधिकारी की रिपोर्ट को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाए गए कुल नौ आरोप, अधिकतर लापरवाही के आरोप या इस आरोप से संबंधित हैं कि उसने अपीलों पर निर्णय लेते समय अपनी न्यायिक शक्ति का लापरवाही से प्रयोग किया। जाँच अधिकारी द्वारा प्रत्येक आरोप के संदर्भ में दर्ज किए गए किसी भी निष्कर्ष में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंगित करता हो कि जाँच अधिकारी की राय में भी, यह गंभीर कदाचार का मामला था।

24. एच.एल. गुलाटी बनाम भारत संघ एवं अन्य (सिविल अपील संख्या **8224-8225**, वर्ष **2011**) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर, सक्षम प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह इस पहलू पर वर्तमान मामले की तुलना में अधिक गंभीरता से विचार करे। "आरोपों की गंभीरता को देखते हुए" यह कहना पर्याप्त नहीं है।

25. हमने विभिन्न आरोपों पर भी गौर किया है जो लगाए गए थे और सिद्ध पाए गए। दो आरोपों को छोड़कर, अन्य आरोप लापरवाही के आरोपों से संबंधित हैं और मोटे तौर पर, ऐसा प्रतीत होता है

कि अधीनस्थ अधिकारी ने कुछ आदेश पारित किए थे और वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप लापरवाही का ही है। इसके अलावा, अन्य दो आरोप अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अर्ध-न्यायिक शक्ति के प्रयोग से संबंधित हैं। यह स्थापित कानूनी स्थिति है कि सामान्यतः न्यायिक शक्ति का प्रयोग कदाचार नहीं माना जाता है।

26. रवि यशवंत भोईर बनाम जिला कलेक्टर, रायगढ़ एवं अन्य, **(2012) 4 एससीसी 407** में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन अपवादों को हटा दिया है जिनमें अर्ध-न्यायिक कार्य को भी कदाचार के रूप में वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। रवि यशवंत भोईर (सुप्रा) के मामले में, सिद्धांत को इस प्रकार समझाया गया था:

"13. केवल निर्णय की त्रुटि जिसके परिणामस्वरूप लापरवाहीपूर्ण कार्य हुआ हो, कदाचार नहीं माना जाता। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, लगन से काम न करना भी कदाचार माना जा सकता है। ऐसा कार्य जो संस्था की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक हो, वह भी कदाचार माना जा सकता है। अधिकार से परे कार्य करना भी कदाचार माना जा सकता है। जब किसी पदाधिकारी से कार्य को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करने की अपेक्षा की जाती है, तब धन आदि का कोई भी दुरुपयोग, चाहे वह अस्थायी ही क्यों न हो, गंभीर कदाचार माना जाता है, जिसके लिए कड़ी सजा दी जा सकती है।"

27. वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि जांच अधिकारी ने भी इन कानूनी पहलुओं पर गौर नहीं किया है और न्यायिक आदेश की सत्यता और वैधता को नजरअंदाज कर इसे कदाचार का मामला मान लिया है।

28. परिस्थितियों और आरोपों की प्रकृति, जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और वर्तमान परिस्थितियों या सामग्री पर विचार न करने के कारण, इस बात पर संतोष व्यक्त किया जा सकता है कि वर्तमान मामला गंभीर कदाचार या गंभीर लापरवाही के रूप में वर्गीकृत किए जाने योग्य है, हमारी राय में, अपीलकर्ता की पूरी पेंशन, वह भी उसके जीवनकाल के लिए, रोकने का आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यह आदेश शक्ति के अतिरेक से ग्रस्त है और कानून में इसे बनाए नहीं रखा जा सकता।

29. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस कानूनी पहलू को उचित रूप से नहीं समझा गया, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश हस्तक्षेप योग्य है और इसे रद्द किया जाता है।

30. तदनुसार, दिनांक 08.12.2000 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। विचारणीय अगला प्रश्न यह है कि इस स्तर पर अपीलकर्ता को क्या राहत प्रदान की जानी चाहिए। अभिलेखों से पता चलता है कि जब जाँच लंबित थी, अपीलकर्ता 29.02.1996 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया और उसे 30.11.2000 तक अनंतिम पेंशन का भुगतान किया गया। स्पष्टतः, चूँकि 08.12.2000 को पेंशन रोकने का आदेश पारित किया गया था, उसके बाद उसकी पेंशन रोक दी गई। 24 वर्ष बीत चुके हैं। यदि यह मामला लंबे समय से लंबित न होता, तो हम इस मामले को नए सिरे से विचार के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास पुनः भेजते और नए आदेश पारित करते। हालाँकि, इस समय, यदि मामले को वापस भेजा जाता है और अधिकारियों को अपीलकर्ता, जो 90 वर्ष के करीब है और पिछले 24 वर्षों से अपनी पेंशन से वंचित है, के मामले में कोई भी आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है, तो यह न्याय के हित में नहीं होगा। इसलिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, हम इस मामले को आगे रिमांड के बिना यहीं समाप्त करना चाहते हैं।

31. मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता उस पेंशन का 50% पाने का हकदार होगा जो उसे विवादित आदेश के बिना मिल सकती थी। इस आदेश की तिथि से, वह बिना किसी रोक के पूर्ण पेंशन पाने का हकदार होगा, जैसा कि 08.12.2000 के आदेश में कहा गया था, जो हमारे द्वारा पारित आदेश के आलोक में अब मान्य नहीं है। आवश्यक कार्यवाही तीन महीने की अवधि के भीतर की जाए।

32. अपील स्वीकार की जाती है और अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका भी, तदनुसार, ऊपर वर्णित तरीके और सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

33. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(आशुतोष कुमार), जे

(मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव),

सीजे रजत/तनिषा/41

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी